दैनिक जागरण
धर्म आत्मा-परमात्मा के मध्य संबंध स्थापित करने वाला माध्यम है

ईवीएम विरोध की जिद

कुछ राजनीतिक दल किस तरह गैर जरूरी मसलों को बेवजह लंबा खींचते हैं और ऐसा करके अपना और साथ ही देश का वक्त जाया करते हैं, इसकी ही मिसाल है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की 50 फीसद मतदान बाद की पर्चियों का मिलान करने की जिद। पता नहीं 21 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई इस दलील पर क्या कहेंगे कि 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने से चुनाव नतीजे घोषित होने में छह से नौ दिन की देरी हो सकती है, लेकिन हैरत नहीं कि वे यह कह दें कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद यही जान पड़ता है कि किसी तरह ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा किया जाए। वे एक अर्से से ईवीएम के खिलाफ बिना किसी सुबूत के शरारत भरा अभियान छेड़े हुए हैं। यह अभियान संकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि करीब चार महीने पहले ही कांग्रेस ने तीन राज्यों में भाजपा को पराजित किया है। इसके पहले भी उसने गुजरात में उल्लेखनीय जीत हासिल की थी। तथ्य यह भी है कि अतीत में दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि के चुनाव नतीजे भी ईवीएम से ही निकले थे और उनमें भाजपा की हार हुई थी। इसी तरह 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी ईवीएम आधारित थे। आखिर बीते दो-तीन साल में ऐसा क्या हुआ है कि ईवीएम को बदनाम करने का सिलसिला कायम हो गया है?

ईवीएम को संदिग्ध बताने के लिए किस तरह छल-छद्म का सहारा लेने से भी बाज नहीं आया जा रहा है, इसका एक प्रमाण दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम की नुमाइश से मिला था और अभी हाल में लंदन में एक तथाकथित हैकर के हास्यास्पद दावे से। विडंबना यह है कि ईवीएम विरोधी अभियान को कुछ राजनीतिक दलों के साथ मीडिया का भी एक हिस्सा तूल देता है। बाद में ऐसी दलीलों की आड़ भी ली जाती है कि अब अगर ईवीएम को लेकर संदेह उभर आया है तो फिर उसे दूर किया ही जाना चाहिए। अगर इरादा ही नित-नए संदेह पैदा करना है तो फिर उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। हैरत नहीं कि कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यह मांग करने लगें कि शत प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। ध्यान रहे कि कुछ दल ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं। यह कुछ वैसी ही विचित्र मांग है जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताए। 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने की मांग इसलिए अनावश्यक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग करीब-करीब हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ की मतदान पर्चियों का मिलान करता है। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आखिर जब इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं मिली तब फिर 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों के मिलान की मांग का क्या मतलब? यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं का निपटारा करना ही होता है, लेकिन उसे यह भी देखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का मूल मकसद क्या है?

केंद्रीय बल पर खींचतान

विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल के सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। भाजपा ने तो सभी बूथों को संवेदनशील घोषित कर चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जाहिर है सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनात करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। सभी राज्यों में जरूरत के मुताबिक केंद्रीय बल तैनात करने पड़ेंगे। ऐसे में केंद्रीय बल की कमी पड़ ही सकती है। गृह मंत्रालय केंद्रीय बल की भरपाई के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल के जंगलमहल यानी नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात केंद्रीय बल की 35 कंपनियों को हटा कर उसे चुनाव कार्य में लगाना चाहता है। इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने जंगलमहल क्षेत्र से केंद्रीय बल हटाने के गृह मंत्रालय के निर्णय पर आपत्ति जताई है। सरकार ने गृहमंत्रालय को पत्र लिखकर जंगलमहल से केंद्रीय बल नहीं हटाने का अनुरोध किया है। अब सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि राज्य को विश्वास में लिए बिना केंद्र जंगलमहल से केंद्रीय बल नहीं हटा सकता है। बेशक सरकार को कानून व्यस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए राज्य में केंद्रीय बल की मदद लेने का अधिकार है। लेकिन चुनाव के समय राज्य के सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। चुनाव आयोग को जहां जितनी जरूरत पड़ेगी वहां उतनी संख्या में केंद्रीय बल तैनात करेगा। अब गृह मंत्रालय चुनाव के समय राज्य के जंगलमहल से केंद्रीय बल हटाने की जरूरत महसूस कर रहा है तो इस पर राज्य को आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी गृह मंत्रालय ने जंगलमहल से केंद्रीय बल हटा कर अन्य राज्यों में ले जाने की बात नहीं कही है। उन्हें राज्य में ही चुनावी जरूरतों के अनुसार तैनात करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा करती हैं कि जंगलमहल शांत है और पहाड़ हंस रहा है। लेकिन दोनों जगह केंद्रीय बल तैनात हैं। ऐसी स्थिति में वहां केंद्रीय बल रखने पर सवाल उठ सकता है।

राहुल के वायनाड जाने का मतलब

एमजे अकबर

आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई कांग्रेस अध्यक्ष जीत के लिए मुस्लिम लीग पर निर्भर होगा। जरा इसके संभावित असर के बारे में विचार करें

अगर अमेठी सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कांग्रेस अपने लिए किसी सीट को सुरक्षित नहीं मान सकती। कभी राहुल गांधी ने खुद ज्यूपिटर की 'एस्केप वेलोसिटी' जैसा हैरतअंगेज शिगूफा छेड़ा था तो लगभग उसी अंदाज में उनका यह कदम भी हैरान करने वाला है कि वह उत्तर प्रदेश में परिवार की अपनी पारंपरिक सीट से एक तरह किनारा करके सुदूर दक्षिण में केरल की पहाड़ियों के बीच बसे वायनाड में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने जा रहे हैं। गंगा-यमुना के मैदान में बसी हिंदी पट्टी में कांग्रेस के पराभव और भग्नावशेष राजनीतिक खुदकशी से जुड़ा महत्वपूर्ण विमर्श है। यह अपने आप में इतना बड़ा है कि खुद एक किताब लिखे जाने की मांग करता है, मगर वह एक अलग मसला है।

राहुल गांधी का अमेठी से पलायन वर्ष 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के खाते में दर्ज होने वाली पहली हार की तरह है। यहां यह स्मरण करना भी उल्लेखनीय होगा कि अमेठी में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने वह सब किया जो वे कर सकते थे। बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही एलान कर दिया था कि वे अमेठी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन जब केमिस्ट्री या यूं कहें जन-जुड़ाव ही निर्णायक हो जाता है तो बड़े से बड़े गणितीय आकलन धरे के धरे रह जाते हैं। अमेठी के मतदाता एक लंबे अरसे से किए जा रहे थोथे वादों से अब उकता गए हैं और विकास के मोर्चे पर पिछड़ने को लेकर भी वे कुपित हो रहे हैं। यह मायावती और अखिलेश के उस फैसले को भी जायज ठहराता है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को अपने गठबंधन से बाहर रखना ही मुनासिब समझा। कांग्रेस ने इसमें शामिल होने के लिए एड़ी-चोटी के जोर तो लगाए, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।

यह एक उलझी हुई पहेली ही है कि आखिर वायनाड ही क्यों? किसी भी कद्दावर नेता के लिए यह बहुत सामान्य माना जाता है कि वह उस राज्य से चुनाव लड़े जहां उनके दल की सरकार हो। यह बहुत ही सामान्य चलन है। इसकी वजह यह है कि अपनी पार्टी की सरकार में प्रशासन कई अप्रत्यक्ष तरीकों से सहायक होता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही है। हाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे तीन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बनीं हैं। वास्तव में जब चार महीने पहले कांग्रेस ने इन राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी तो पार्टी समर्थकों ने राजनीतिक क्षितिज पर सूरज की एक नई किरण के रूप में इसका स्वागत करते हुए कहा था कि 2019 के चुनाव तक यह दोपहर के चढ़े सूरज की मानिंद अपनी चमक बिखेरेगा।

आखिर राहुल गांधी ने इन राज्यों से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों पर विश्वास नहीं है या फिर उन्हें यह अहसास हो गया है कि मतदाताओं का पहले से ही मोहभंग हो रहा है? कर्नाटक पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। बेंगलुरु में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में कांग्रेस ही वर्चस्व वाली भूमिका में है। जनता दल-सेक्युलर के पुरोधा एचडी देवगौड़ा को अपनी निजी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस के सहारे की दरकार है।

इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं। जब 1977 के लोकसभा चुनावों में हुए मानमर्दन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस का कायाकल्प करने में जुटी थीं तो 1978 में कर्नाटक का चिकमंगलूर ही उनका राजनीतिक पड़ाव बना था। तब वह चिकमंगलूर के रास्ते ही संसद पहुंची थीं। हाल में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने भी राहुल गांधी को अपने राज्य से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। इसके लिए बीदर सीट का नाम भी लिया जा रहा था। ऐसे आमंत्रण पहले से किसी सलाह-मशविरे के बिना नहीं भेजे जाते। आखिरकार अंत में कर्नाटक से कन्नी क्यों काट ली गई?

अवधेश राजपूत

एक बार फिर इसका जवाब भी बहुत ही स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी अब कर्नाटक को अपना बहुत मजबूत किला नहीं मानती है और यही राय उसके नेताओं की भी है। अब जब चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ रहा है तो हम दीवार पर लिखी इबारत को भी स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। जमीनी हकीकत तो यही बयान कर रही है कि जनसमर्थन का ज्वार प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बढ़ रहा है।

तब फिर वायनाड ही क्यों? यह कम दिलचस्प नहीं है कि वायनाड में राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी रण में उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके इस एक कदम से वामपंथियों का दिल टूट गया है। वे लाल-पीले हो रहे हैं। एक नेता के रूप में राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए वामपंथी दलों से जो भी बन पड़ा, उन्होंने किया। उनका इतिहास अनिश्चितता, गलतियों और गलत फैसलों भरा रहा है। वामपंथी दलों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि इसका उन्हें यह सिला मिलेगा कि राहुल गांधी उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल लेंगे। यह वही राहुल गांधी हैं जो सभी साथी राजनीतिक दलों के बीच यह कहते हुए घूम रहे थे कि भाजपा को हराने के लिए वे सभी आपसी मतभेद भुलाकर उसे सत्ता से बाहर करने में सहायक बनें। इस सबके बीच इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि केरल में इस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ नहीं, बल्कि मार्क्सवादी मोर्चे की सरकार है तो कांग्रेस को कोई प्रशासनिक लाभ भी नहीं मिलेगा।

राहुल गांधी के वायनाड से भी चुनाव लड़ने के फैसले का केवल एक ही कारण है और वह यह कि इस संसदीय क्षेत्र में करीब आधे मतदाता मुस्लिम हैं। इसमें कुछ हर्ज नहीं। भारतीय मुस्लिम देश के वोटर हैं और उन्हें अपनी पसंद तय करने का अधिकार है। इस धारणा का कोई आधार नहीं कि मुस्लिम वोटर एक जैसे हैं। वे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल में अलग-अलग तरीके से वोट करते हैं। वायनाड में मसलमानों का एक तबका भाकपा के साथ हैं। वहां भाकपा प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, लेकिन केरल और खासतौर पर वायनाड में अधिकांश मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। राहुल गांधी को जीत के लिए मुस्लिम लीग पर निर्भर रहना होगा। कांग्रेस चाहे तो अपने नेतृत्व वाले मोर्चे यूडीएफ की जीत के आंकड़े का स्मरण कर सकती है। दरअसल जो दल उसकी मदद कर सकता है वह मुस्लिम लीग ही है। यह इतिहास में पहली बार होगा जब कोई कांग्रेस अध्यक्ष जीत के लिए मुस्लिम लीग पर निर्भर होगा। जरा इसके संभावित असर के बारे में विचार करें।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मील के पत्थर कायम करता इसरो

शुकदेव प्रसाद

बीते पांच दिनों की इसरो की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि भारत अंतरिक्ष के मोर्चे पर महाशक्ति बन गया है

पांच दिन पहले रक्षा अनुसंधान में एक गौरवमयी उपलब्धि के बाद इसरो ने एक और कीर्तिमान रचा। इसरो के ध्रुवीय राकेट पीएसएलवी-सी45 ने पहली बार विभिन्न पेलोड को तीन विभिन्न कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस राकेट ने भारतीय उपग्रह 'एमिसेट' को 749 किमी की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया। यह भारत का पहला उपग्रह है जो सेना के लिए अंतरिक्ष से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस उपग्रह को 'इसरो' के अध्यक्ष के. सिवन ने 'आकाश में सेना की आंख' की संज्ञा दी है। इस मिशन का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि इसरो के इतिहास में यह सबसे लंबी उड़ान है जो तीन घंटे में समाप्त हुई। उपग्रह एमिसैट को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद ध्रुवीय राकेट के चौथे चरण (पीएस 4) के इंजन को बंद कर दिया गया। प्रायः एक घंटे के बाद इसकी मोटर को फिर प्रज्जवलित किया गया। इसके बाद इसने चार देशों के 28 लघु उपग्रहों को 504 किमी की निम्न कक्षा में स्थापित किया। इनमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड और लिथुअनिया जैसे देशों के उपग्रह हैं। खास बात यह है कि यह सारा काम मात्र पांच मिनट में संपन्न हो गया। सामन्य प्रक्रिया यह है कि राकेट का चौथा चरण भी जलकर विनष्ट हो जाता है, लेकिन इस बार इस चरण को कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। यह तीसरा अवसर है जब हम पीएसएलवी के चौथे चरण को अंतरिक्ष संबंधी परीक्षणों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले छह महीने तक यह चौथा चरण अंतरिक्ष आधारित प्रयोगों के लिए देश को अपनी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। इसरो ने इस प्रक्षेपण में एक और कीर्तिमान बनाया। इस उड़ान में ध्रुवीय राकेट का नव संस्करण इस्तेमाल किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक मेधा से संपन्न है। इसे पीएसएलवी-क्यू एल नाम दिया है। अब ध्रुवीय राकेट के तीन मॉडल हमारे पास हैं जो क्रमशः स्टैंडर्ड माडल, कोर एलोन और एक्स-एल (एक्स्ट्रा लार्ज) कहलाते हैं, लेकिन पहली बार इसरो ने ध्रुवीय राकेट के प्रथम चरण के साथ चार स्ट्रैपआन मोटरों का इस्तेमाल किया है। इस उड़ान के साथ इसरो ने मील का एक और पत्थर कायम किया है।

हमारा ध्रुवीय राकेट अपने चौथे चरण के साथ जो प्रयोग करेगा उसमें पहला प्रयोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है जो आयन मंडल का अध्ययन करेगा। यह भी पहली बार संभव हुआ कि इस संस्थान ने अपना पेलोड अंतरिक्ष में भेजा। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि भारत अब अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान में महारत हासिल कर चुका है। भारत ने जो अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की हैं उनसे भारत का गौरव वर्द्धन ही नहीं हुआ, अपितु उसने

विकसित देशों के समक्ष एक नया उदाहरण पेश किया है। ऐसा ही उदाहरण 27 मार्च को तब पेश किया गया था जब ए-सैट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। दरअसल जब कोई उपग्रह बेकार हो जाता है या उसके सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं तो उसकी कक्षा क्रमशः छोटी होने लगती है। ऐसे में वह ज्यों-ज्यों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है तो पृथ्वी के बढ़ते गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन इससे एक खतरा भी पैदा हो जाता है। दरअसल उसमें भरे हुए रासायनिक पदार्थ अत्यंत घातक होते हैं जो मनुष्य समेत अन्य जीवधारियों के स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। इस समस्या के निदान के लिए हाल के वर्षों में कुछ राष्ट्रों ने एंटी-सैटेलाइट मिसाइलों का विकास किया है। इसके जरिये उन्होंने धरती की ओर आ रहे ऐसे उपग्रहों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि भारत ने पहले प्रयास में ही ऐसी सफलता प्राप्त कर ली।

विगत में अमेरिका और रूस ने भी शीत युद्ध के दौरान ऐसी क्षमता अर्जित की थी। चीन ने भी ऐसी क्षमता 2007 में अर्जित कर ली थी। अमेरिकी स्टार वार्स (नक्षत्र युद्ध) की तर्ज पर भारत ने अपना यह कार्यक्रम 2008-09 में ही आरंभ कर दिया था। हालांकि अमेरिका इस प्रणाली को आज तक तैनात नहीं कर सका है। जब रोनाल्ड रीगन ने इसको आरंभ किया था तो परीक्षण के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल क्वाजालीन अटाल दक्षिण प्रशांत से दागी गई। वहां से 7700 किलोमीटर दूर वेंडनबर्ग हवाई अड्डे से एक एंटी मिसाइल ने उड़ान भरी और धरती पर गिरने से पूर्व ही हवा में उसे मार गिराया। यह प्रणाली तैनात होती कि एक बड़ी घटना घट गई। हुआ यह कि अमेरिकी शटल चैलेंजर ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंडों बाद उसमें आग लग गई। उसी के साथ उसमें सवार सातों अंतरिक्ष यात्री भी जलकर खाक हो गए। अतः इस प्रणाली को अविश्वनीय करार देते हुए रीगन ने निरस्त कर दिया। आगे चलकर बिल क्लिंटन जब अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसको समाप्त करने का एलान किया, लेकिन जाते-जाते उनका राष्ट्रवाद जोर मारने लगा तो उन्होंने इसे नेशनल मिसाइल डिफेंस नाम से पुनः आरंभ किया, मगर दुर्भाग्यवश एक परीक्षण के दौरान उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के बूस्टर अलग ही नहीं हुए और वह औंधे मुंह सागर में जा समाई। फलस्वरूप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ने वेंडनबर्ग हवाई अड्डे से उड़ान ही नहीं भरी। बिल क्लिंटन को जब यह सूचना मिली तो वह एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। वहीं से उन्होंने यह बयान जारी किया कि चूंकि यह प्रणाली अभी परिपक्व नहीं हुई है अतः फिलहाल हम इसे स्थगित कर रहे हैं।

भारत ने अपनी प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम (बीएमडीएस) नाम दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि शत्रु की तरफ से आने वाली मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पूर्व उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया जाए, भले ही वे परमाणु बमों से लैस ही क्यों न हों। भारत की इस प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली की दो श्रेणिया हैं। पहली श्रेणी में लक्ष्य 2000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली मिसाइलों को आकाश में ध्वस्त करना है और दूसरी श्रेणी में ऐसी मिसाइलों को नष्ट करना है जो 5000 किलोमीटर की दूरी से आ रही हों। इसके अलावा भारत की प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली द्विस्तरीय है। इसका उद्देश्य यह है कि दुश्मन की ओर से आ रही मिसाइल को 50 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर मार गिराया जाए। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा न हो सके तो उसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिरा दिया जाए। भारत की प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली द्विचरणीय है और अमेरिकी प्रणाली एक चरणीय। इसमें दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के बाहर ही नष्ट करना होता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली अमेरिकी प्रणाली से श्रेष्ठ है।

(लेखक विज्ञान मामलों के लेखक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं की तलाश

बात उस समय की है जब सुदूर दक्षिणपूर्व एशिया के देशों में सभ्यता का विकास द्रुत गति से हो रहा था। खंडहरों को तेजी से तोड़ा जा रहा था, कस्बों, गांवों के स्वरूप को आधुनिकता के लबादे में तब्दील किया जा रहा था और शहरों को सभ्य, सुसंस्कृत और समृद्ध बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही थी। पुनर्निर्माण के कार्य के इस क्रम में श्रमिकों ने भूमि की खुदाई से एक विशालकाय शिलाखंड ढूंढ निकाला। जिज्ञासावश जब उस शिलाखंड को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो पहली छेनी के प्रहार से ही एक तेज रोशनी प्रस्फुटित हुई। जिज्ञासा और भी प्रबल होती गई और उसके साथ ही उस शिलाखंड को तोड़ने की कोशिशें भी तेज होती चली गईं। पत्थर से काफी मलबे को हटाने के पश्चात उस शिलाखंड से गौतम बुद्ध की एक तेजस्वी स्वर्णिम प्रतिमा अनावृत्त हुई।

सच पूछिए तो शिलाखंड से गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण एक अद्भुत घटना है और इसमें छुपे हुए संदेश प्रेरणा से ओतप्रोत हैं। संजीदगी से विचार करें तो यह समझते देर नहीं लगती है कि इस सृष्टि में हर व्यक्ति के प्रारब्ध की कहानी उस शिलाखंड से कतई भी इतर नहीं है जिसके तराशने के बाद बुद्ध की प्रतिमा का सृजन हो पाता है। किंतु दुर्भाग्यवश हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं और अपने जीवन में अनावृत्त बुद्धत्व को अज्ञानतावश जाया कर जाते हैं।

पुराणों में भी कहा गया है, 'अहम् ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूं। निहितार्थ यह है कि इस संसार का हर व्यक्ति ब्रह्म का अवतार होता है, लेकिन मानव में ब्रह्म और बुद्धत्व की खोज का मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए उसे खुद में बुद्ध की खोज करनी पड़ेगी। ब्रह्म निर्माण के लिए उसे स्वयं की शिद्दत से तलाश करनी होगी। मानवीय कमजोरियों के रूप में लोभ, तृष्णा, मोह-माया और विविध प्रकार के लौकिक बंधनों से खुद को मुक्त करने की दरकार है। शिलाखंड के स्वरूप ही बुद्ध को तराशने के लिए खुद में छुपे हुए बाह्य अवगुणों के रूप में बेकार मलबे को तप-त्याग और तपस्या की छेनी से हटाने की जरूरत है। जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, वही दिन मानव में बुद्ध के सृजन और ब्रह्म के अवतार का दिन होगा।

श्रीप्रकाश शर्मा

रिमोट चलाने का आनंद!

भाई ट्राई वालों हमारे रिमोट चलाने का आनंद हमसे मत छीनो, हम तो इसी के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं!

हाथ में टीवी का रिमोट होना ही महसूस करा देता है कि घर की सत्ता हमारे हाथ में है। कभी घर की दादी पूजा कर रही होती थीं, पूजा की घंटी बजाते-बजाते भी निर्देश देती थीं कि बहू दूध देख लेना, कहीं उफन न जाए, पोते को कहतीं कि बेटा जरा मेरा चश्मा पकड़ा जाना, फिर जोर से बेटे को आवाज लगातीं कि जाते समय मेरी दवा लाना भूल मत जाना। दादी पूजा घर में हैं, लेकिन पूरे घर का रिमोट उनके हाथों में है। अब दादी वाले घर तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन मन बहलाने को रिमोट हाथ आ गया है, जैसे ही पतिदेव के हाथ लगता है, बटन दबते ही जाते हैं और जब तक 100-50 चैनल बदल लिए नहीं जाते तब तक समाचार देखना संभव नहीं होता। पतिदेव रिमोट से चैनल बदल रहे होते हैं और पत्नी अलमारी में से साड़ियों को हाथों से सरका रही होती है, यह नहीं, यह भी नहीं! 10-20 को जब तक परे धकेल नहीं देती तब तक साड़ी का चयन नहीं होता। बच्चे खिलौनों में उलझे हैं, सारे ही खिलौने कमरे में फैले हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा और छोटा बच्चा रसोई में जा पहुंचता है, कटोरी-चम्मच को बजाने से जो आवाज आती है, बस वही उसका आनंद है। ढेर सारी चीजों में से अपनी पसंद चुनना हमारी आदत है। यदि चुनने का अधिकार नहीं मिला तो लगता है जीवन ही बेकार गया। सब्जी वाले की दुकान जब तक सब्जी से भरी न हो तो क्या खाक सब्जी खरीदने का आनंद है!

इन दिनों ट्राई ने यह आनंद छीन लिया है, कहते हैं कि जो चैनल देखने हों, बस उतने ही रखो और पैसे बचाने के मजे लो। हुआ यूं कि कुछ बुजुर्गवारों ने कहा कि हम तो केवल दाल-रोटी ही खाते हैं तो भला 56 भोगों वाली पूरी थाली के पैसे क्यों दें! दूसरे ने कहा कि सच कह रहे हो, मैं तो टीवी पर केवल समाचार ही देखता हूं तो भला 1000 चैनल के पैसे क्यों दूं! पहुंच गए ट्राई के दरबार में, मुकदमा दर्ज करा दिया। ट्राई ने कहा कि सच है आप पूरे पैसे क्यों देंगे! फरमान जारी हो गया कि जितने चैनल देखते हो, बस उतने का ही पैसा दो। बड़ा अच्छा लगा, सुनने में। अब दो दो-चार चैनल के ही पैसे देंगे। लेकिन यह क्या! जो रिमोट घुमाते थे, उनका तो खेल ही समाप्त हो गया! ऐसे लगने लगा जैसे बोइंग विमान की जगह हेलिकॉप्टर में यात्रा कर रहे हों। चैलन तो वहीं अटक गया। अब घुमा लो अपनी अंगुलियों पर दुनिया को! सारा मिजाज ही ठंडा पड़ गया। आनंद ही समाप्त हो गया।

माना कि अपने घर का ही खाना खाना है, लेकिन आसपास के घरों में ताक-झांक करके खाने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि टीवी पुराने दूरदर्शन का डिब्बा हो गया। समाचार देख लो और कृषि दर्शन देख लो। देखना हमें चार ही है, लेकिन भरी पूरी दुकान से ही सौदा खरीदेंगे ना! भाई ट्राई वालों हमारे रिमोट चलाने का आनंद हमसे मत छीनो, हम तो इसी के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं! जैसे ही हमारे हाथ में भूले भटके से रिमोट आता था हम कहीं की महारानी बन जाते थे, हमें भी रिजेक्ट करने का और चयन करने का सुख मिल जाता था। घर में ही पुस्तकालय बना रखा था, जब मन करता किताब उठाकर पढ़ लेते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप सीमित रूप से ही किताबें रख सकेंगे, कौन सी किताब छाटूं और कौन सी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है।

(अजित गुप्ता का कोना ब्लॉग से साभार)

मेलबाक्स

पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का वक्त

बिगड़ैल पड़ोसी पर हो निर्णायक प्रहार शीर्षक से लिखे अपने लेख में ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत को उसके पड़ोसी देशों को उसके विरोध में खड़ा करने की नीति अमल में लाने की जरूरत बताई है, लेकिन जब तक चीन और अमेरिका पाकिस्तान के किसी न किसी रूप में हमदर्द बने रहेंगे तब तक यह बिगड़ैल पड़ोसी हमारे लिए सिरदर्द बना रहेगा। भारत को इसके लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए कि अमेरिका तथा चीन भी पाकिस्तान के विरोधी बनें और उसकी मदद करना बंद करें, लेकिन यह तभी संभव है, जब ये दोनों देश विश्वव्यापी समस्या आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया छोड़ें और अपनी कथनी-करनी में एका लाएं। इसके साथ ही अन्य मुस्लिम देशों को भी पाकिस्तान के विरोध में खड़ा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान द्वारा आतंकी पाले जाने के कारण दूसरे मुस्लिम देशों की छवि खराब न हो।

raju09023693142@yahoo.com

गायब होती खुशी

हाल ही में आई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स-2019 की 156 देशों की सूची में भारत को 140वां स्थान मिला है और यह पिछले वर्ष की तुलना में सात पायदान नीचे है। यही नहीं, हमारी उदासी का आलम यह है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी इस मामले में काफी पीछे हैं। इस सूची में पाकिस्तान अपनी रैंकिंग में पिछले साल से सुधार करते हुए 75वें स्थान से 67वें पर आ गया है। स्वस्थ्य जीवन प्रत्याशा, आजादी और भ्रष्टाचार की समाप्ति जैसे छह पैमानों को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली इस सूची में हम लगातार पिछड़ क्यों रहे हैं? इस सवाल की जवाबदेही जितनी सरकार की है उतनी आम नागरिक की भी है। कहीं हम द्वेष में सुलग कर उग्र तो नहीं होते जा रहे हैं। खुशियों के बिना जिंदगी अधूरी है। भारत को एक खुशहाल राष्ट्र का दर्जा तो दिलाना ही चाहिए।

संजय दूबे, नई दिल्ली

वोट की शक्ति

युवा मतदाताओं को जागरूक होना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है। उनको अपने अधिकारों और दायित्वों का अहसास कराना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ा सकते हैं। वोट की शक्ति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मतदान सबसे प्रभावी जरिया है। इस दायित्व का अहसास युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को होना बहुत जरूरी है।

रवि पांडेय, फरीदाबाद

महिला अधिकारी की हत्या

अभी पंजाब में एक महिला अधिकारी की निर्मम हत्या इसलिए कर दी गई कि उन्होंने कई साल पहले एक दवा की दुकान का लाइसेंस निरस्त किया था। इस दुकान में कुछ अवैध दवाई बेचे जाने की बात सामने आई थी। इस तरह की घटनाएं अन्य शहरों में भी हो चुकी हैं, जब ईमानदार अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन की सजा मिली है। जो अधिकारी सम्मान के पात्र होते हैं, उन्हें चाहे माफिया या अन्य लोग प्रताड़ित करते हैं। देश से भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण देना होगा।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

गलत फैसला

राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शायद उन्होंने जनता का मिजाज भांप लिया है, इसीलिए केरल में सुरक्षित सीट चुनी है। इसका चुनाव की दृष्टि से नकारात्मक संदेश जाएगा। अमेठी में जो मतदाता कांग्रेस को वोट देने का मन बनाए होगा, उसका मन बदल सकता है। वायनाड में राहुल गांधी जीत भी जाएं तो भी कांग्रेस पार्टी को इस फैसले से नुकसान ही होगा।

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

प्रचार में कलाकार

आज नेताओं के भाषण उतने प्रभावी नहीं हैं, जिनके बल पर वे वोट को खींच सकें। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां विभिन्न कलाकारों को अपने साथ जोड़ रही हैं, जिनसे मतदाताओं को मंत्रमुग्ध किया जा सके। यह स्थिति हर पार्टी की है। कलाकारों पर निर्भरता का कारण नेताओं का अपने कर्तव्यबोध का अभाव होना भी है।

mahesh_nenava@yahoo.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा व्यक्त हमें पत्र

mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय सं-
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन